Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, MARCH 1, 2014
(PHALGUNA 10, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 1st March, 2014

No. 18—HLA of 2014/18.—The Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 2014 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 18—HLA of 2014

THE HARYANA RURAL DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 2014

A

Bill

further to amend the Haryana Rural Development Act, 1986.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Rural Development (Amendment) Act, 2014. Short title.

Amendment of section 5 of Haryana Act 6 of 1986.

2. In sub-section (1) of section 5 of the Haryana Rural Development Act, 1986,—

(i) in the fourth proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) after the fourth proviso, the following proviso shall be added at the end, namely :—

"Provided further that from the date of notification of the Haryana Rural Development (Amendment) Act, 2014, no fee shall be charged on vegetables and fruits, as mentioned in Schedule under clause (b) of rule 2 of the Haryana Rural Development Rules, 1987.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to give relief to the vegetables and fruits growers and the public, the State Government proposes that rural development fee shall not be charged on vegetables and fruits.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 1st March, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 18 - एच० एल० ए०

हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2014

**हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986,
को आगे संशोधित करने
के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

1986 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 5 का संशोधन।

2. हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 5 की उप-धारा (1) में,–

(i) चतुर्थ परन्तुक में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, " : " चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) चतुर्थ परन्तुक के बाद, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2014 की अधिसूचना की तिथि से हरियाणा ग्रामीण विकास नियम, 1987 के नियम 2 के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूची में यथावर्णित सब्जियों तथा फलों पर कोई भी फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

फलों तथा सब्जियों के उत्पादकों तथा जनता को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार फलों और सब्जियों पर से ग्रामीण विकास शुल्क न लगाने का प्रस्ताव करती है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 1 मार्च, 2014.

सुमित कुमार,
सचिव।

52091—H.V.S —H.G.P., Chd.